संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 22 जून, 2018 : द्वि. ज्येष्ठ शुक्ल 10 वि. 2075

प्रार्थना हृदय की पुकार है

बैंकों के विलय का समय

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय पर चर्चा को आगे बढ़ाना समय की मांग और जरूरत है। यह अच्छा हुआ कि कोयला एवं रेल मंत्रालय के साथ वित्त मंत्रालय का भी काम देख रहे पीयूष गोयल ने बैंकों के विलय के सवाल पर सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से विचार-विमर्श किया। बैंकों के विलय के सवाल को और अधिक टालने का मतलब इसलिए नहीं, क्योंकि इस पर लंबे समय से विचार-विमर्श ही हो रहा है। बैंकों के विलय को लेकर पहले वाजपेयी सरकार के समय विचार हुआ और फिर मनमोहन सरकार के समय भी, लेकिन किन्हीं कारणों से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। अगर तभी कोई फैसला ले लिया गया होता तो शायद आज सरकारी क्षेत्र के बैंक उन तमाम समस्याओं से नहीं जूझ रहे होते जिनसे वे बुरी तरह घिरे हुए हैं। यदि बैंकों के विलय के विचार को समय रहते अमल में ले आया गया होता तो शायद आज एनपीए के रूप में फंसे कर्ज की समस्या भी इतना गंभीर रूप नहीं ले पाती। बीते कुछ समय से स्थिति यह है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक केवल अपने एनपीए के कारण ही चर्चा में हैं। निःसंदेह बैंकों को एनपीए के संकट से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन इसी के साथ उन्हें कार्यकुशल और जवाबदेह भी बनना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी समझना होगा कि उनका एक बुनियादी काम कर्ज बांटना भी है। चूंकि इधर एक अर्से से बैंकों पर एनपीए संकट को हल करने का दबाव है इसलिए वे लोन देने में जरूरत से ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। इस अतिरिक्त सतर्कता के चलते कारोबारियों को लोन मिलने में कठिनाई हो रही थी। ऐसे में यह जरूरी था कि कोई बैंकों को यह याद दिलाता कि सतर्कता बरतने का मतलब लोन देने से इन्कार करना नहीं हो सकता।

अगर बैंकों से लोन मिलना कठिन हो जाएगा तो फिर कारोबार और अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति कैसे मिलेगी? यह अच्छा है कि बतौर वित्तमंत्री पीयूष गोयल के हस्तक्षेप के बाद स्थिति बदलती दिख रही है, लेकिन इस धारणा को दूर करने की जरूरत है कि घोटालों के सिलसिले के बाद सरकारी बैंकों से लोन लेना कठिन हो गया है। जहां तक बैंकों के विलय की बात है, बतौर वित्त मंत्री पीयूष गोयल के लिए इस अधूरे एजेंडे को पूरा करने में इसलिए आसानी होनी चाहिए, क्योंकि वह मंत्रियों के उस दल का हिस्सा हैं जिसे सरकारी बैंकों के विलय पर आने वाले प्रस्तावों पर अंतिम फैसला करना था। बैंकों के विलय के काम को इसलिए वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि एक तरह से वह समय सीमा खत्म हो चुकी है जिसमें कोई फैसला ले लिया जाना था। निःसंदेह भारत एक बड़ा देश है और अन्य क्षेत्रों की तरह बैंकिंग क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्द्धा आवश्यक है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सरकारी बैंकों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो। 20 से अधिक बैंकों का कोई औचित्य नहीं बनता। इतने अधिक बैंक तो निगरानी के काम को जटिल ही बनाते होंगे। बैंकों को विलय की राह पर ले जाने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे नई कार्यसंस्कृति से लैस हों।

फसल बीमा की विफलता

प्रधानमंत्री फसल बीमा केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, पर कतिपय कारणों से अब यह बदहाल है। दो वर्षों में इस योजना में महज डेढ़ से दो फीसद किसानों का ही बीमा हो पाया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो खरीफ वर्ष 2016 में सिर्फ 35.84 लाख किसानों का ही बीमा हुआ। वर्ष 2017 में यह संख्या घटकर 25.56 लाख हो गई। यह आंकड़ा कुल किसानों का मात्र डेढ़ से दो फीसद है। इसे लेकर अब सवाल बीमा कंपनियों पर उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस योजना से बीमा कंपनियां मालामाल हो रही हैं। जबकि इनका किसी जिले में न तो कार्यालय है और न ही कोई सर्वे तंत्र। इतनी महत्वाकांक्षी योजना का ठीक से प्रचार-प्रचार भी नहीं किया गया है।

एक बात तो स्पष्ट है कि किसी भी योजना की विफलता का ठीकरा किसी न किसी पर फोड़ने की परंपरा बन गई है।

एक बात तो स्पष्ट है कि किसी भी योजना की विफलता का ठीकरा किसी न किसी पर फोड़ने की परंपरा बन गई है। जब सरकार इसे अपनी महत्वाकांक्षी योजना मानती है तो उसे किस आंकड़े का इंतजार है। रबी हो या खरीफ की फसल, गन्ने से लेकर अन्य नकदी फसलों की भी खरीद सरकारी या उसके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं या व्यवस्था के माध्यम से होती है। मतलब यह कि किसानों के पर्याप्त आंकड़े सरकार के पास होते हैं, तो फिर इसमें प्रचार-प्रसार करने वाली क्या बात है। इसे अनिवार्य रूप से सभी के लिए लागू कर दिया जाना चाहिए। जिन किसानों की उपज की सरकारी खरीद होगी, उन किसानों को इस योजना से जोड़ने में कहां दिक्कत आ रही है। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो बीमा के प्रावधान में कहीं न कहीं खोट है, जिसमें बदलाव की जरूरत है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन के बाद आतंक के खिलाफ अभियान में तेजी आएगी?

आज का सवाल
क्या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बाद योग को लेकर जागरूकता बढ़ी है?

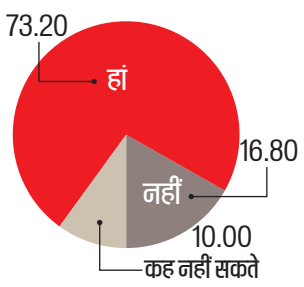

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

हमारे एजेंडे पर आए गिलगित-बाल्टिस्तान

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान को अपना पांचवां प्रांत घोषित कर वहां की जनसांख्यिकी में बदलाव के साथ ही चीन को खुश करना चाहता है

हाल में पाकिस्तान कैबिनेट ने उस फैसले पर मुहर लगा दी जिसके तहत गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) उसका पांचवां प्रांत कहलाएगा। यह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान अवैध रूप से काबिज है। भारत ने इस पर कड़ा प्रतिरोध जताते हुए कहा कि 1947 की विलय संधि के आधार पर जीबी सहित जम्मू-कश्मीर का समूचा भाग भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने भारत के इस दावे को खारिज कर दिया। पाकिस्तान कैबिनेट के उक्त फैसले के खिलाफ जीबी में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। दुर्भाग्यवश मीडिया में इसे बहुत तवज्जो नहीं मिली। जम्मू-कश्मीर की स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च 1816 तक समूचा जम्मू, कश्मीर घाटी, लद्दाख और बाल्टिस्तान सिख साम्राज्य का हिस्सा था। 1842 में सिख सेना ने पश्चिमी तिब्बत को कब्जा लिया। फिर चीनी-तिब्बती सेना के जवाबी हमले के बाद सिख सेना को लद्दाख लौटना पड़ा और तीन सितंबर, 1843 को चुशूल की संधि हुई। दोनों पक्ष भविष्य में परंपरागत सीमा का सम्मान करने पर राजी हुए। 1846 में पहले आंग्ल-सिख युद्ध में जम्मू के राजा गुलाब सिंह ने सैन्य हमले में जानबूझकर देरी की और इसका नतीजा अंग्रेजों की जीत के रूप में निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और बाल्टिस्तान के इलाके सिख साम्राज्य से हड़प लिए और गुलाब सिंह को सौगात के रूप में दे दिए। 16 मार्च 1846 को हुई अमृतसर की संधि में गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का शासक बनाया गया। इसके एवज में उन्हें 75 लाख नानकशाही रुपये देना तय हुआ, लेकिन उन्होंने लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था इसलिए यह रकम घटाकर 16 लाख रुपये कर दी गई। गुलाब सिंह के उत्तराधिकारियों ने बाद में इसमें हुंजा, पुनेल, यासिन, अस्तोर, चितराल, नागर, इश्कोमन, कुह-गिजर और चिलास को भी शामिल किया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के अनुसार अन्य रजवाड़ों की तरह जम्मू-कश्मीर को भी यह विकल्प मिला था कि वह भारत या पाकिस्तान में किसी के साथ भी मिल जाए या खुद को स्वतंत्र घोषित करे। महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने के विकल्प को चुना। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ यथास्थिति की पेशकश की। जल्द ही पाकिस्तान ने पुंछ में हमले को शह दी और 22 अक्टूबर को अपनी सेना के सहयोग से जम्मू-कश्मीर में कबायली घुसपैठ शुरू करा दी। महाराजा ने भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई। भारत ने इसके लिए कुछ शर्तें रखीं। उन्हें स्वीकार करने के बाद ही नेहरू ने सैन्य मदद मुहैया कराई। 26-27 अक्टूबर को विलय की संधि पर हस्ताक्षर के साथ जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा बना। शेख अब्दुल्ला को आपात प्रशासन का प्रमुख नियुक्त किया गया। भारतीय सैनिक 27 अक्टूबर को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे और कश्मीर घाटी को घुसपैठियों से मुक्त कराया। 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए जम्मू-कश्मीर को छह भू-राजनीतिक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख पर भारत का नियंत्रण है। वहीं जीबी और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके पाकिस्तान के पास है। छठा हिस्सा अक्साई चिन चीन के कब्जे में है। पाकिस्तान ने जीबी का हिस्सा रही शक्सगम घाटी चीन को दोस्ती की सौगात के रूप में अवैध रूप से सौंपी। पीओके का कुल क्षेत्रफल 13,297 वर्ग किमी और मुजफ्फराबाद उसकी राजधानी है। यहां बहुसंख्यक आबादी सुन्नियों की है। यह इलाका अक्सर आतंकी गतिविधियों के कारण खबरों में रहता है।

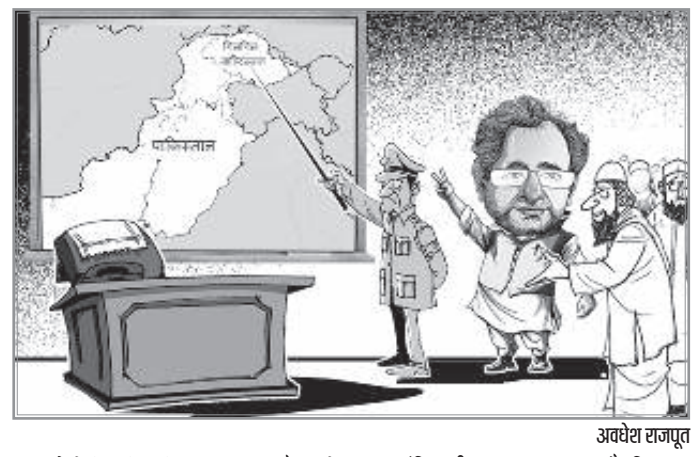

अवधेश राजपूत

इसके उलट जीबी 72,971 वर्ग किमी में फैला बड़ा इलाका है जो सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तमाम कीमती खनिज मौजूद हैं। पनबिजली में भी यहां अकूत संभावनाएं हैं और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की मुख्य कड़ी कराकोरम हाईवे यहीं से गुजर रहा है। सुन्नी बहुल पाकिस्तान और पीओके के उलट जीबी में शिया, नूरबख्शी और इस्माइली बहुतायत में हैं और सुन्नियों की आबादी 28 फीसद है। पाकिस्तान पंजाबी सुन्नियों को यहां बसाकर इलाके की जनसांख्यिकी बदलना चाहता है जिसका स्थानीय लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

पाकिस्तान ने सेना और आदिवासियों के हमले से पीओके हासिल किया, लेकिन नवंबर, 1947 में उसके हाथ जीबी की कमान ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की मिलीभगत से लगी। गिलगित की सामरिक अहमियत और सोवियत रूस के हमले की आशंका को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने 1935 में गिलगित को महाराजा से पट्टे पर लिया। उसका प्रशासन दिल्ली से एक ब्रिटिश अधिकारी के माध्यम से चलता था। उसकी सुरक्षा का जिम्मा ब्रिटिश अधिकारियों वाली गिलगित स्काउट्स के पास था। आजादी के साथ ही अंग्रेजों ने पट्टे को रद करते हुए 1 अगस्त, 1947 को गिलगित महाराजा को वापस लौटा दिया। महाराजा ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह को जीबी का गवर्नर बनाया। उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी मेजर डब्लू ए ब्राउन की सेवाएं भी मिलीं। जैसे ही महाराजा का झुकाव भारत की ओर बढ़ा वैसे ही ब्राउन ने घनसार सिंह की हत्या कर दी और अपने पूर्ववर्ती ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट को जीबी के पाकिस्तान में विलय की सूचना दी। 2 नवंबर को मेजर ब्राउन ने पाकिस्तानी झंडा फहराकर पाकिस्तान की सेवा में सक्रिय होने का दावा किया। 16 नवंबर को पाकिस्तान ने उन्हें अपना राजनीतिक दूत नियुक्त किया और स्कार्दू, द्रास, कारगिल और लेह पर हमले के लिए जीबी को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया। ब्राउन ने तकनीकी रूप से विद्रोह किया था, जिसके लिए वह सजाए मौत के हकदार थे। वह पाकिस्तान के साथ गहरा जुड़ाव रखते थे और पाकिस्तान छोड़ने की उनकी इच्छा नहीं थी। सेना से पदमुक्त होने के बाद वह कोई बड़ा पद चाह रहे थे। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज में उनकी नियुक्ति हुई और 1949 में उन्हें कोलकाता में तैनाती मिल गई। नेहरू ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन सिखों ने उन्हें नहीं बख्शा, क्योंकि वे उन्हें बुंजी में छठी कश्मीर इन्फैंट्री में सिखों के दस्ते को खत्म करने का कसूरवार मानते थे। एक दिन वह शहर की सड़क पर अधमरे मिले, लेकिन एक डॉक्टर को मिल गए जिनकी मेहरबानी से उनकी जान बच गई।

जीबी पर पाकिस्तानी कब्जे को स्थानीय लोग कभी नहीं पचा पाए। अब वह उसे अपना पांचवां प्रांत घोषित कर वहां की जनसांख्यिकी में बदलाव के साथ ही चीन को खुश करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले के प्राचीर से यहां के लोगों पर पाकिस्तानी अत्याचारों का जिक्र किया था तो उन्हें एक उम्मीद बंधी थी। हालांकि उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहां अलगाववाद की चिंगारी सुलग रही है। भारत का दायित्व बनता है कि वह स्थानीय लोगों को नैतिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से मदद मुहैया कराए। अगर भारत जीबी में लोगों से वैसे ही जुड़े जैसे पाकिस्तान कश्मीर में जुड़ गया है तो उसकी आजादी का रास्ता खुल सकता है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही सबक सिखाने की जरूरत है।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

दावों के उलट है खेती की हालत

राजीव सातव

आखिर सरकार किसानों को सस्ते एवं सरल कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराने की कोई ठोस पहल क्यों नहीं कर रही है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों फिर यह कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए बजट में कृषि क्षेत्र को दोगुनी रकम का प्रावधान किया गया है। उनके अनुसार यह राशि दो लाख 12 हजार करोड़ रुपये हैं, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों की आत्महत्या का सिलसिला कायम है। अन्नदाता रह-रह कर सड़कों पर भी उतर रहे हैं। इस मुश्किल समय में भी सरकारी उदासीनता साफ दिख रही है। एक आंकड़े के अनुसार देश में हर दिन करीब 35 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वर्ष 2014-15 में 12360 किसानों ने आत्महत्या की। 2015-16 में यह संख्या 12602 हो गई। 2016-17 में 11458 और 2017-18 में 14000। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए ठोस कदम उठाना तो दूर रहा, मोदी सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के लिए तैयार नहीं। किसानों की चीख जुमले की राजनीति में गुम होती जा रही है। मौजूदा सरकार के विपरीत कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने हमेशा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत को एक कमजोर कृषि क्षेत्र विरासत में प्राप्त हुआ था। खेती के समक्ष कई तरह की चुनौतियां थीं। उनसे निपटने के लिए प्रभावी और कुशल नीति की जरुरत थी। फलतः तत्कालीन नीति-निर्माताओं ने प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के साथ कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद लगभग प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कुछ न कुछ प्रावधान अवश्य किए गए। 1960 के दशक में हरित क्रांति के साथ कृषि क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसने न केवल भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि भारत को एक खाद्यान्न निर्यातक देश के रूप में भी स्थापित किया। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कृषि नीतियों के स्तर पर भी कई उपाय किए गए। इसके साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की भी पहल की गई, किंतु मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज अन्नदाता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते आम चुनाव के समय किसानों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में उनकी सरकार लगातार नाकाम हो रही है। अगर आंकड़ों के आधार पर बात करें तो मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल यानी 2014 से 2018 के बीच कृषि वृद्धि दर कांग्रेस काल यानी 2004 से 2014 के 4.2 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 1.9 प्रतिशत पर आ चुकी है।

मोदी सरकार का वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी एक जुमला साबित हो रहा है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक कंपाउंड वार्षिक ग्रोथ रेट

(सीएजीआर) 10.4 प्रतिशत होनी चाहिए जबकि यह 2.5 प्रतिशत ही है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि में भारी कमी आई है। यह 2014 मे जहां 38 प्रतिशत थी वहीं 2018 में यह शून्य प्रतिशत पर आ गई है। मनरेगा के कार्य दिवसों में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। 2014 में यह 45 दिन था जबकि 2018 में यह 16.3 पर आ गया। मनरेगा में मजदूरी के भुगतान की स्थिति भी ठीक नहीं। अप्रैल 2018 तक करीब 99 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत में 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर निर्धारित किया जाएगा, लेकिन खरीफ सत्र की किसी भी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वादा पूरा नहीं किया गया। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने 89 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था किंतु आधार से जुड़े 30 लाख किसानों का भी कर्ज माफ नहीं किया गया। कर्ज माफी के नाम पर उत्तर प्रदेश में 11700 किसानों के एक रुपये से लेकर 500 रुपये तक के कर्जे माफ किए गए।

वैसे तो सभी किसान संकट में हैं, लेकिन गन्ना किसानों की स्थिति कहीं अधिक दयनीय है। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया जाएगा, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। गन्ना किसानों की बकाया राशि करीब 20000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री के वादे के 11 महीने बाद उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बकाया राशि12224 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। मोदी सरकार किसानों के साथ आर्थिक एवं सामाजिक आधार पर कैसे धोखाधड़ी कर रही है, इसका सटीक उदाहरण फसल बीमा योजना है। जितना प्रीमियम इसमें जमा किया गया उससे काफी कम आर्थिक सहायता गरीब किसानों को प्राप्त हुई। 2016 में खरीफ और 2016-17 में रबी की फसल के दौरान 20478 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा हुआ। इसमें से किसानों को केवल 5650 करोड़ रुपये का लाभ मिला और कंपनियों ने इससे 14828 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। एक विडंबना यह भी है कि जीएसटी के दायरे में ट्रैक्टर और कृषि से संबंधित अन्य उपकरण भी शामिल हैं। कृषि निर्यात की जगह आयात बढ़ गया है। वर्ष 2013-14 में कुल 43.23 अरब डॉलर का निर्यात हुआ और 15.03 अरब डॉलर का आयात। वर्ष 2014-15 में 39.06 अरब डॉलर का निर्यात हुआ और 20.62 अरब डॉलर का आयात। 2015-16 में निर्यात घट कर 32.79 अरब डॉलर रह गया और आयात बढ़कर 22.06 अरब डॉलर का हो गया। 2016-17 में निर्यात का आंकड़ा 33.87 अरब डॉलर का और आयात का 25.09 अरब डॉलर हो गया। आखिर इसे देखते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि खेती की हालत सुधर रही है?

किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार सामने आने के बाद भी सरकार यह मानने को तैयार नहीं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार की उपेक्षा के चलते किसान और खेती, दोनों अपनी अहमियत तेजी के साथ खो रहे हैं। किसानों की उन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है जिनके चलते अन्नदाता आत्महत्या को मजबूर हैं। सरकार जन-धन योजना के जरिये वित्तीय समावेशन के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। वह मुद्रा योजना, स्टार्ट अप योजना का भी जिक्र कर रही है, लेकिन उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं कि किसानों की कर्ज आपूर्ति के लिए कोई बड़ी योजना क्यों नहीं है? समझना कठिन है कि आखिर यह सरकार किसानों को सस्ते एवं सरल कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराने की कोई ठोस पहल क्यों नहीं कर रही है? चूंकि अधिकांश किसानों की सरकारी वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच नहीं है इसलिए वे साहूकारों के मोटे ब्याज वाले कर्ज के जाल में फंस रहे हैं।

(लेखक कांग्रेस के लोकसभा सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय

सफलता प्राप्त करने लिए कर्म के साथ ही समय-प्रबंधन बेहद जरूरी है। उचित समय पर किया गया कर्म हमेशा फलदायी होता है। जो व्यक्ति तय समय पर अपना काम नहीं करते, उनकी सफलता संदिग्ध ही रहती है। इसलिए लक्ष्य निर्धारण के साथ व्यक्ति को समय-प्रबंधन का भी ध्यान रखना चाहिए। कई लोग यह शिकायत करते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है, जबकि यह बिल्कुल सच नहीं है। हम सभी के पास एक समान समय होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं और असफल लोग ज्यादातर समय अपने दुखों और परेशानियों का ही रोना रोते रहते हैं। सफल वही लोग होते हैं, जो लक्ष्य तय करने और उसकी प्राप्ति के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। ऐसे लोगों को यह मालूम होता है कि उन्हें किस और कितने समय में अपने कार्यों को पूरा करना है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग असफल होते ही नहीं हैं, लेकिन वे अपनी असफलता से भी बहुत कुछ सीखते हैं और निरंतर कोशिश करते रहते हैं।

समय-प्रबंधन का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान गलतियां नहीं करेगा। इंसान से गलतियां होना स्वभाविक बात है, लेकिन कभी कोई गलती हो जाने के बाद हमें तुरंत उसमें सुधार करना चाहिए। इसके साथ ही हमें काम करने के दौरान उसका आकलन भी करते रहना चाहिए कि जैसा हमने सोचा था, क्या काम उसी के अनुरूप हो रहा है। ऐसे आकलन से हम अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। मनुष्य को एक समय में एक ही काम करना चाहिए। एक साथ कई काम करने से कभी-कभी कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता है। इसके विपरीत जब हम एक मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है और हम कम समय में सार्थक कार्य करते हैं। इसी तरह हमें जो काम सरल लगता है, उसे पहले करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भी हम अपना काफी समय बचा सकते हैं। इसी के साथ हमें नहीं कहना भी आना चाहिए। असल में हर व्यक्ति की कार्य करने की एक क्षमता होती है। ऐसे में हमें अपना उतना ही काम तय करना चाहिए, जितना हम निश्चित समय में सफलतापूर्वक कर सकें। अन्यथा काम का ज्यादा बोझ मनुष्य के दिमाग में दबाव उत्पन्न करता है, जिससे उसका सारा काम प्रभावित हो सकता है।

शंभूनाथ पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

सेहत का विज्ञान है योग

योग के पथ पर बढ़ती दुनिया शीर्षक से लिखे अपने लेख में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी बताया है। वास्तव में योग हर आयु वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, बशर्ते कि नियमित और संयमित ढंग से किया जाए। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया अर्थात सुखी रहने के लिए हमारा स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए योग भी एक कारक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। योग एक कला है जो मन, मस्तिष्क एवं शरीर पर नियंत्रण रखने में सहायक है। योग इसलिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि वर्तमान भागमभाग जिंदगी में जीवनशैली और खानपान में असंतुलन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से तमाम युवा भी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं जो कि चिंता का विषय है। किसी भी देश का विकास युवाओं के कंधे पर होता है और इसलिए युवाओं का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। योग का लाभ भी तभी होगा जब नियमित दिनचर्या का यह हिस्सा बनेगा अन्यथा कि स्थिति में अन्य दिवसों की भांति इसका भी हश्र होगा अर्थात यह भी 21 जून तक ही सिमट गया तो कोई सकारात्मक और सार्थक परिणाम की आशा कम ही है।

सर्वजीत आर्या, कन्नौज

पीपल को लेकर अंधविश्वास

आज भी देश में अंधविश्वासी लोगों की कमी नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ पर भूत-प्रेत रहते हैं। वे इस पेड़ को घर के आसपास या दरवाजे पर लगाने से बचते हैं, जबकि वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है , कि पीपल का पेड़ प्रकृति में अन्य सभी पेड़ों से मानव मात्र के लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद है। यह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाला एक मात्र वृक्ष है, जो रात में भी और पेड़ों के विपरीत ऑक्सीजन देता है। भूत-प्रेत की बातें अंधविश्वासी और भ्रामक हैं।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

योग जीवन का हिस्सा

योग मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है, इसलिए साल के सबसे लंबे दिन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग भले ही देश में प्राचीनतम रहा हो, परंतु लोगों में इसके प्रति रुझान बाबा राम देव की ही देन है। योग मन मस्तिष्क व शरीर को स्वस्थ व चिंता से मुक्त रखता है। आज के प्रदूषण भरे समय में योग को जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि नित्य योग करने से अनेको बीमारियों का अंत होता है।

sakshiguptaw8042000@gmail.com

दूर हुई भ्रांतियां

कुलदीप नैयर का लेख, याद रहे सेक्युलर संविधान, पढ़कर भारतीय लोकतंत्र पर फिर एक बार गर्व हुआ। अपने आसपास के देशों में विरोधी विचारधारा वालों के विरुद्ध दिन रात हिंसा की खबरों के बीच देश की सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह द्वारा एक ऐसे पत्रकार से मिलना जिनका दर्शन हमेशा से भाजपा के विपरीत रहा है, बेहद प्रशंसनीय है। इस मुलाकात ने कुलदीप नैय्यर के मन में अमित शाह के प्रति व्याप्त कई भ्रांतियों को दूर किया। मसलन उनका मानना था कि अमित शाह हमेशा आग उगलते रहने वाले गुस्सैल नेता हैं, लेकिन मुलाकात के पश्चात वे उनकी नम्रता व मिलनसार स्वभाव के कायल हो गए। बेशक नैयर ने भाजपा सरकार के विरुद्ध अपनी राय को अमित शाह के समक्ष रखा, लेकिन परिणामस्वरूप कोई क्लेश नहीं हुआ बल्कि अमित शाह ने बेहद आत्मीयता के साथ कुलदीप नैयर के संदेह को दूर करने की कोशिश की।

snehabh20141983@gmail.com

संगीत भी एक तरह का योग

यह कितना सुखद संयोग रहा कि अंतराष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही अंतराष्ट्रीय संगीत दिवस भी था। योग और संगीत दोनों एक साधना हैं। दोनों ही विश्व को जोड़ने के साथ ही हमें अध्यात्म एवं परमात्मा से जोड़ते हैं और दिखावे की दुनिया से अलग रखते हैं। योग में शक्ति है हमारी काया को निरोगी रखने की। संगीत में शक्ति होती है कई असाध्य रोगों को कम करने की। म्यूजिक थेरेपी इसी को कहते हैं। संगीत भी अपने आप में एक योग ही है। विश्व भर के संगीत और विभिन्न संगीत की शैलियों को एक दूसरे के बारे में जानने और समझने की नींव ब्रिटेन में रखी गई थी, लेकिन आज विश्व संगीत दिवस की धूम भारत में भी खूब है। आज हम हर तरह के संगीत को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उन्हें समझते भी हैं। इस बात को हम नकार नहीं सकते कि विश्व संगीत का असर हमारे संगीत पर भी हुआ है। संगीत सरहदों के परे है। दुनिया भर के संगीतकार आज एकदूसरे से प्रेरित होकर उम्दा संगीत रच रहे हैं। संगीत में ही वह शक्ति है जो मनुष्यता को बचाए हुए है। हमें संगीत से मिल रहे संदेशों को समझना होगा कि किस तरह भांति -भांति के स्वर, राग, वाद्य यंत्र आदि मिलकर एक बेहद खूबसूरत संगीत रचते हैं, ठीक उसी तरह इस संसार में भांति -भांति के हम लोग भी मिलकर एक बेहतर और प्रेम से परिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। संगीत सोचने की क्षमता और रचनात्मकता का विकास करता है। वह हममें तर्क करने, समस्याओं से निपटने की योग्यता को बढ़ाता है। संगीत की परिभाषा बस इतनी सी है कि यह वो सरल भाषा है जिससे दुनिया के किसी भी भाग और इंसान के बारे में, वहां की सभ्यता एवं संस्कृति को समझा जा सकता है।

अभिषेक अवस्थी, नोएडा

ट्वीट-ट्वीट

आइएसआइ से जुड़े एक ब्लॉग पर उन लोगों की हिट लिस्ट है जो कश्मीर में तथाकथित 'आजादी की लड़ाई' में अड़ंगा बने हुए हैं। शुजात बुखारी की हत्या से हफ्ता भर पहले उनका नाम भी डाला गया था। मैं इन बातों से नहीं डरने वाला और सच कहने से नहीं हिचकूंगा। जुनैद कुरैशी@JQ_plaintalk

लगता है कि पासपोर्ट मामले को लखनऊ के युगल ने धार्मिक रंग देकर लोगों को बेवकूफ ही बनाया। शायद मसला अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ा हो, लेकिन खबरों के भूखे मीडिया के लिए उन्होंने मामले को ऐसे परोसकर जल्द पासपोर्ट बनवाकर अपना काम आसान कर लिया। शिव अरूर@ShivAroor

बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य से देश की दशा बदली जरूर जा सकती है, लेकिन नाकाम सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली और नाकाम सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में केवल खर्च बढ़ाकर ही सुधार नहीं किया जा सकता। नीतियों में आमूलचूल बदलाव और संस्थागत सुधारों से ही इन्हें दुरुस्त कर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

अरविंद विरमानी@dravirmani

अंतरराष्ट्रीय योग दि